

सं० ओ० वि०/यमुना नगर/25-87/31745.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) चीफ इन्जि० हार्डिल प्रोजेक्ट, हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, गोविन्दपुरी, यमुनानगर, (3) कार्यकारी अभियन्ता, चैनल नं० 2, हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, भूडकलां, डा० खिजराबाद, जिला अम्बाला के श्रमिक श्री बाबू राम, पुत्र श्री केवल राम, मार्फत डा० सुरेन्द्र कुमार शर्मा, महान् मन्त्री, इन्टक धर्मशाला ब्राह्मण रेलवे रोड़, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामलें में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 (44)84-3 अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बाबू राम शर्मा की सेवाओं का समापन/छंटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/यमुना नगर/23-87/31753.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि सचिव, हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, चण्डीगढ़ (2) चीफ इन्जि० हार्डिल प्रोजेक्ट, हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, गोविन्दपुरी, यमुनानगर, (3) कार्यकारी अभियन्ता, चैनल नं० 2, हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, भूडकलां, डा० खिजराबाद, जिला अम्बाला के श्रमिक श्री बुच्चा राम, पुत्र श्री दलपत राम, मार्फत डा० सुरेन्द्र कुमार शर्मा, महान् मन्त्री, इन्टक धर्मशाला ब्राह्मण रेलवे रोड़, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामलें में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 (44)84-3 अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बुच्चा राम, की सेवा समाप्ति/छंटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/यमुना नगर/32-87/31761.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) चीफ इन्जि० हार्डिल प्रोजेक्ट, हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, गोविन्दपुरी, यमुनानगर, (3) कार्यकारी अभियन्ता, चैनल नं० 2, हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, भूडकलां, डा० खिजराबाद, जिला अम्बाला के श्रमिक श्री शब्बीर खान, पुत्र श्री रसीद खान, मार्फत डा० सुरेन्द्र कुमार शर्मा, महान् मन्त्री, इन्टक धर्मशाला ब्राह्मण रेलवे रोड़, जगाधरी, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामलें में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)-84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री शब्बीर खान की सेवाओं का समापन/छंटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?